IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 4, October-December, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय बालिका शिक्षा: एक आलोचनात्मक अध्ययन (बिहार राज्य के शासकीय पहल एवं राजनीतिक विमर्श के विशेष संदर्भ में)

जयनाथ चौधरी
पीएच.डी. शोधार्थी
शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
jnch251290@gmail.com

सारांश (Abstract)

बालिकाओं/महिलाओं की साक्षरता दर में विगत कुछ दशकों में राष्ट्रीय और राजकीय दोनों स्तरों पर तेज सुधार/वृद्धि अंकित की गयी है। जो राष्ट्रीय और राजकीय सरकारों के सराहनीय प्रयासों को दर्शाती है। इसी संदर्भ में, यदि बात बिहार राज्य विशेष कि की जाए तो गत दो दशकों में, बिहार ने महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार/वृद्धि दर्ज की है, जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक दशकीय सुधारों/वृद्धि में से एक है। फिर भी, यह सुधार गंभीर सवालों और विरोधाभासों को जन्म देती है, क्योंकि यह राज्य आज भी राष्ट्रीय शैक्षिक सूचकांकों में, विशेषकर सकल नामांकन दर (GER), शुद्ध नामांकन दर (NER), और विद्यालयी ठहराव (Retention) दर में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। यह शोध पत्र इन्हीं सवालों और विरोधाभासों की गहन पड़ताल करते हुये, बिहार राज्य विशेष में उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर, सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा की बहुआयामी स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसके अलावा, यह शोध अध्ययन राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव तथा इन शैक्षिक सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के इर्द-गिर्द विकसित हुये राजनीतिक विमर्शों के अंतर संबंधों को भी उजागर करने का प्रयास करता है। जिसके लिए यह शोध अध्ययन अपने तीन प्रमुख उद्देश्यों को ले कर अग्रसर होता है। और उसकी पूर्ति के लिए द्वितीयक स्रोतों पर आधारित गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग करता है। जिसके अंतर्गत यह विभिन्न प्रकार के नीतिगत एवं तथ्यपरक सरकारी दस्तावेजों, आँकड़ों, अकादमिक शोध-पत्रों आदि के विश्लेषणों से प्राप्त तथ्यों व आँकड़ों का संश्लेषण कर एक समग्र और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

निष्कर्षतः प्रस्तुत शोध अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि बिहार राज्य बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक ऐतिहासिक वृद्धि दर (अर्थात् लड़कियों की विद्यालय तक पहुँच में) तो सफलता जरूर प्राप्त की है, मगर गुणात्मक सफलता के लक्ष्यों से अभी भी कोसों दूर है। प्रोत्साहन एवं कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण एक ऐसी लोकलुभावन नीति को बढ़ावा देता है, जो प्रतिबद्ध गुणात्मक गहरे शैक्षिक सुधारों के बजाय नामांकन के आँकड़ों को प्राथमिकता देती है। अतः नीतिगत स्तर पर केवल प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर, एक ऐसी समग्र बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयी सुरक्षा, सामंतवादी रूढ़िगत मानसिकता और पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने पर केंद्रित हो।

मुख्य शब्द (Keywords) : बालिका शिक्षा, नामांकन दर, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, वोट बैंक,

परिचय: बिहार का शैक्षिक परिदृश्य और ऐतिहासिक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बीमारू (BIMARU) राज्य का कलंक

बिहार, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की भूमि रहा है और जिसने प्राचीन विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया, आधुनिक काल में एक गंभीर शैक्षिक अंधकार के दौर से गुजरा है। स्वतंत्रता के बाद के कई दशकों तक, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को प्रणालीगत विफलता, जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढाँचे और सामाजिक बहिष्कार के पर्याय के रूप में देखा जाता रहा। 1990 के दशक तक, बिहार को "**बीमारू" (BIMARU - बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश)** राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था, जो खराब आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों का संकेत था।

इस दौर में, विशेष रूप से बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, गरीबी, और विद्यालयी सुरक्षा के अभाव ने लड़कियों को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। शिक्षा को लड़कियों के लिए एक अनावश्यक निवेश माना जाता था, जिसका प्रतिफल केवल **"विवाह बाजार"** में देखा जाता था, न कि **"श्रम बाजार"** में।

2005 के बाद का परिवर्तन और नई उम्मीद

वर्ष 2005 बिहार की राजनीति और सामाजिक नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नई सरकार ने सत्ता में आते ही **"न्याय के साथ विकास"** का नारा दिया और सामाजिक विकास के एजेंडे में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को केंद्रीय स्थान दिया (Kriplani, 2025)। सरकार ने यह पहचाना कि महिला साक्षरता का सीधा संबंध प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर और आर्थिक उत्पादकता जैसे व्यापक संकेतकों से है। इस समझ ने राज्य में **"सकारात्मक भेदभाव" (Positive Discrimination)** और कल्याणकारी वितरण की एक नई लहर को जन्म दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान, बिहार ने महिला साक्षरता में लगभग 20 प्रतिशत अंकों की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की, जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक थी, हालाँकि यह सुधार अत्यंत निम्न आधार (33.57%) से शुरू हुआ था (Gordon, 2021; Sharma, 2023)।

शोध जिज्ञासा के प्रश्न और तर्कसंगतता: सफलता के बीच गहराता संकट

बावजूद इसके कि आँकड़े एक सफलता की कहानी कहते हैं, जमीनी हकीकत जटिल और विरोधाभासी है। आज बिहार राष्ट्रीय शैक्षिक **प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)** में संघर्ष कर रहा है। लड़कियाँ रिकॉर्ड संख्या में स्कूलों में प्रवेश ले रही हैं, सरकार साइकिल और पोशाक के लिए पैसे दे रही है, लेकिन क्या वे वास्तव में सीख रही हैं? क्या वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रही हैं? सकल नामांकन दर (GER) में सुधार के बावजूद, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर और शुद्ध नामांकन दर (NER) के आँकड़े चिंताजनक हैं (UDISE+, 2024-25; Sharma, 2025)।

यू-डाइस+ रिपोर्ट में इसे **"नामांकन-अधिगम विरोधाभास" (Enrollment-Learning Paradox)** के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य ने **"प्रवेश की बाधाओं" (Barriers to Entry)** को तो काफी हद तक स्कूल बनाकर और प्रोत्साहन देकर हटा दिया है। लेकिन, **"जुड़ाव की बाधाओं" (Barriers to Engagement)** को दूर करने में विफलता हाथ लगी है। कक्षाओं के भीतर, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बुनियादी सुविधाओं (जैसे - शौचालय) और रोजगारपरक पाठ्यक्रम के अभाव का सामना करना पड़ता है। यह शोध अध्ययन इन्हीं अंतर्विरोधों की गहन पड़ताल करता है।

शोध के उद्देश्य और प्रकृति

यह शोध अध्ययन निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्यों को ले कर अग्रसर होता है:

1. **मात्रात्मक मूल्यांकन:** नवीनतम सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर बिहार में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन दर , ड्रॉप आउट दर, ठहराव दर और अधिगम प्रतिफलों की वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करना।
2. **नीतिगत समीक्षा:** मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना और कन्या उत्थान योजना जैसी प्रमुख सरकारी पहलों के क्रियान्वयन, प्रभावशीलता और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण करना।
3. **राजनीतिक अर्थव्यवस्था:** बालिका शिक्षा से संबंधित नीतियों व वोट बैंक के राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करना और यह समझना कि क्यों सरकारें संरचनात्मक गुणवत्ता के बजाय लोकलुभावन योजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

शोध की प्रकृति: द्वितीयक स्रोतों पर आधारित गुणात्मक विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक

मात्रात्मक वास्तविकता: नामांकन बनाम ठहराव (Enrollment vs. Retention)

बिहार की बालिका शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए, यहाँ मैंने सर्वप्रथम उपलब्ध सांख्यिकीय आँकड़ों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जो यू-डाइस+ (UDISE+) और अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों द्वारा प्रदान की गई है। ये आँकड़े एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जहाँ "प्रवेश" तो सुलभ है, लेकिन "निकास" और भी अधिक सुगम है।

नामांकन के रुझान: पहुँच में विस्तार

बिहार सरकार की शिक्षा नीति की सबसे बड़ी और दृश्यमान सफलता सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio - GER) में वृद्धि है। यूडीआईएसई+ 2024-25 के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक आँकड़ों के अनुसार, मध्य स्तर (उच्च प्राथमिक) पर का जीईआर (GER) 90.3% है, जो पिछले वर्ष के 89.5% से मामूली वृद्धि दर्शाता है (UDISE+, 2024-25)। माध्यमिक स्तर पर भी यह बढ़कर 68.5% हो गया है (UDISE+, 2024-25)। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि माता-पिता के व्यवहार में एक बुनियादी बदलाव आया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को भी स्कूल भेजना एक सामाजिक मानदंड बनता जा रहा है।

तालिका-1: राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शैक्षिक संकेतक	
शैक्षिक संकेतक (2024-25)	आँकड़े (प्रतिशत/अनुपात)
सकल नामांकन अनुपात (GER) - मध्य स्तर	90.30%
सकल नामांकन अनुपात (GER) - माध्यमिक स्तर	68.50%
संक्रमण दर (Transition Rate) - प्रारंभिक से मध्य	92.20%
संक्रमण दर (Transition Rate) - मध्य से माध्यमिक	86.60%
छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) - उच्च प्राथमिक	17
स्रोत: UDISE+ 2024-25	

प्रारंभिक से मध्य स्तर पर 92.2% और मध्य से माध्यमिक स्तर पर 86.6% की संक्रमण दर (Transition Rate) यह सुझाव देती है कि जो लड़कियाँ कक्षा 8 पास कर लेती हैं, उनमें से अधिकांश कक्षा 9 में प्रवेश ले रही हैं। यह उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि यौवन (Puberty) लड़कियों की स्कूली शिक्षा के लिए एक पूर्ण विराम है।

ड्रॉप आउट का संकट: लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं?

हालाँकि, जीईआर के ये आँकड़े छात्र प्रतिधारण (Retention) की गंभीर वास्तविकता को छिपा लेते हैं। यद्यपि लड़कियाँ नामांकन करवा रही हैं, लेकिन वे अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही बड़ी संख्या में प्रणाली से बाहर हो रही हैं। यूडीआईएसई+ डेटा माध्यमिक स्तर पर 8.2% की ड्रॉप आउट दर दर्शाता है (UDISE+, 2025), लेकिन स्वतंत्र और तुलनात्मक विश्लेषण एक अधिक भयावह तस्वीर पेश करते हैं।

तालिका-2: तुलनात्मक शैक्षिक संकेतक (बिहार बनाम केरल)		
संकेतक	बिहार	केरल
माध्यमिक ड्रॉपआउट दर	25.60%	3.40%
छात्र-शिक्षक अनुपात (माध्यमिक)	30	13
शुद्ध नामांकन अनुपात (माध्यमिक)	27.80%	71.50%
प्रतिधारण दर (Retention Rate) - माध्यमिक	56.70%	98.60%
कंप्यूटर लैब वाले स्कूल	8.30%	68.70%
स्रोत: UDISE+ 2023-24		

मेहता, 2025 के अनुसार, बिहार की माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 25.6% है, जो देश में ओडिशा (25.9%) के बाद दूसरी सबसे खराब स्थिति है (Sharma, 2025)। इसके विपरीत, केरल जैसे राज्य में यह दर मात्र 3.4% है (Mehta, 2025)। यह भारी अंतर यह दर्शाता है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली अपनी छात्राओं को रोके रखने में विफल रही है। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर स्थिति और भी बदतर है, जहाँ ड्रॉप आउट दर 10.3% बनी हुई है (Sharma, 2025)।

"घोस्ट छात्र"' (Ghost Students) की परिघटना: जमीनी रिपोर्टों और वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) से एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह मिलती है कि बिहार में नामांकन और उपस्थिति के बीच भारी अंतर है। कई सरकारी स्कूलों में नामांकन रजिस्टर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाते हैं। छात्र, विशेष रूप से उच्च कक्षाओं में, केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में नामांकन कराते हैं, जबकि वे वास्तव में या तो निजी कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं या घरेलू श्रम में लगे होते हैं (Deeksha, 2024)। असर (ASER) 2022 ने नोट किया कि यद्यपि नामांकन उच्च है, बिहार के स्कूलों में दैनिक उपस्थिति देश में सबसे कम है। 2024 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा "ई-शिक्षा कोष" (e-Shiksha Kosh) ऐप के माध्यम से उपस्थिति पर नज़र रखने की पहल ने बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति का खुलासा किया, जिससे यह पुष्टि होती है कि नामांकन के आँकड़े शैक्षिक जुड़ाव का विश्वसनीय पैमाना नहीं हैं (Paran Amitava & Sharma, 2024; *ASER 2022 National Findings,* 2023)।

उच्च माध्यमिक स्तर पर लैंगिक अंतराल

जैसे-जैसे छात्राएँ उच्च स्तर की ओर बढ़ती हैं, एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आती है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर लैंगिक अंतराल कम हुआ है (और कुछ संकेतकों में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ भी दिया है), उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर यह अंतराल फिर से चौड़ा हो जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जीईआर (GER) तेजी से गिरकर 56.2% हो जाता है (Mehta, 2024)। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों का (GER) जीईआर (58.2%) लड़कों (54.4%) से अधिक है, लेकिन बिहार में कॉलेजों में संक्रमण (transition) एक बड़ी बाधा बना हुआ है।

माध्यमिक स्तर पर बिहार की शुद्ध नामांकन दर (NER) केवल 27.8% है, जबकि केरल में यह 71.5% है (Mehta, 2025)। एनईआर (NER) का इतना कम होना (विशेषकर जीईआर की तुलना में) यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में उम्र

के अनुसार उपयुक्त लड़कियाँ स्कूल में नहीं हैं। वे या तो अधिक उम्र (Over-age) की छात्राएँ हैं, जो निचली कक्षाओं में फँसी हुई हैं, या उन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दी है। यह प्रणाली की अक्षमता का एक निंदनीय उदाहरण या बुरा आरोप (damning indictment) है।

गुणवत्ता का संकट: "बिना सीखे स्कूली शिक्षा" (Schooling without Learning)

यदि 20वीं सदी का पैमाना **"नामांकन"** था, तो 21वीं सदी का पैमाना **"अधिगम प्रतिफल"** (Learning Outcomes) है। इस क्षेत्र में, बिहार एक आपातकाल का सामना कर रहा है। असर (ASER) 2023 की **"बियॉन्ड बेसिक्स" (Beyond Basics) रिपोर्ट**, जिसने 14-18 वर्ष के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया, राज्य के लिए एक गंभीर वास्तविकता की जाँच प्रदान करती है।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का अभाव

असर रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के युवाओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात बुनियादी कौशल से वंचित है।

तालिका 3: असर (ASER) 2023 अधिगम स्तर (बिहार ग्रामीण)	
मूल्यांकित कौशल (कक्षा 5 के छात्र)	कार्य करने में सक्षम प्रतिशत (%)
कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ना	41.20%
साधारण भाग (Division) करना	36.20%
अंग्रेजी वाक्य पढ़ना	25% (अनुमानित)
स्रोत: ASER 2023 रिपोर्ट	

- **पठन कौशल:** 2024 में, सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के केवल 41.2% छात्र कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे। हालाँकि यह 2022 के 37.1% से एक सुधार है, इसका अर्थ यह है कि लगभग 60% छात्र पाँच साल की स्कूली शिक्षा के बाद भी बुनियादी स्तर पर पढ़ने में सक्षम नहीं हैं (Kumar, 2025)। यह स्थिति माध्यमिक स्तर पर पहुँचने वाली लड़कियों के लिए एक कमजोर नींव का निर्माण करती है।
- **अंकगणित:** गणित में स्थिति और भी अधिक अनिश्चित है। केवल 36.2% बच्चे एक साधारण भाग (division) का प्रश्न हल कर पाए (Kumar, 2025)।

यह **"अधिगम निर्धनता" (Learning Poverty)** भविष्य के अवसरों को असमान रूप से प्रभावित करती है। यदि एक 14 वर्षीय लड़की एक साधारण वाक्य नहीं पढ़ सकती या बुनियादी गणना नहीं कर सकती, तो उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और औपचारिक श्रम बाजार तक उसकी पहुँच प्रभावी रूप से बंद हो जाती है, भले ही उसके पास सरकार द्वारा प्रदान की गई साइकिल हो।

अधिगम की लैंगिक प्रकृति (Gendered Nature of Learning)

यद्यपि लड़कियों ने नामांकन में लड़कों की बराबरी कर ली है, फिर भी अधिगम प्रतिफलों में, विशेष रूप से कठिन विषयों। जैसे-एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में, एक स्पष्ट **लैंगिक अंतराल** बना हुआ है।

- **गणित और अंग्रेजी: असर 2023** बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में, लड़के अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, समय बताने या वित्तीय गणना करने में लड़के लड़कियों की तुलना में काफी अधिक सक्षम पाए गए (Baig, 2024; Team, 2024)।
- **"सॉफ्ट" विषयों का जाल:** नामांकन के पैटर्न बताते हैं कि 14-18 आयु वर्ग की अधिकांश लड़कियाँ (55.7%) कला/मानविकी (Arts/Humanities) विषयों में समूहीकृत हैं, जबकि लड़के एसटीईएम (STEM) विषयों में (पुरुषों के लिए 36.3% बनाम महिलाओं के लिए 28.1%) (ASER, 2023; Team, 2024) ।

विषयों के चयन का यह अलगाव या भेद एक **"अदृश्य पाठ्यक्रम" (Hidden Curriculum)** अर्थात **पितृसत्ता का अदृश्य पाठ्यक्रम** की ओर इशारा करता है। परिवार और स्कूल सूक्ष्म (या प्रत्यक्ष) रूप से लड़कियों को कला विषयों की ओर धकेलते हैं। इस धारणा के तहत कि ये विषय "आसान" हैं या उसके भविष्य की भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो पेशेवर करियर के बजाय घरेलू कार्यों को प्राथमिकता देती है। एसटीईएम (STEM) में लड़कियों की कमी भविष्य के श्रम बाजार में लैंगिक वेतन अंतराल (Wage Gap) को बढ़ाती है, जिससे महिलाएँ कम वेतन वाले क्षेत्रों तक सीमित रह जाती हैं।

शिक्षक गुणवत्ता और जवाबदेही

शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से शिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ी है। इस संबंध में बिहार पुरानी बीमारियों से ग्रस्त है:

- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):** यद्यपि कई क्षेत्रों में आधिकारिक पीटीआर में सुधार हुआ है, शिक्षक अनुपस्थिति के कारण 'प्रभावी' पीटीआर बहुत खराब है। 2024 की रिपोर्टों ने रेखांकित किया है कि हालिया डिजिटल निगरानी प्रयासों के बावजूद शिक्षक अनुपस्थिति एक गंभीर चुनौती बनी हुई है (Deeksha, 2024; Kumar, 2025)।
- **शिक्षक क्षमता:** पिछले एक दशक में "नियोजित शिक्षकों" (संविदा शिक्षकों) पर निर्भरता ने, जिन्हें अक्सर कम योग्यता और वेतन पर रखा जाता है, गुणवत्ता को मात्रा के साथ बदल दिया है। हालाँकि इससे रिक्तियाँ तेजी से भरी गईं, लेकिन इसने ऐसे शिक्षकों का एक वर्ग तैयार किया, जो अक्सर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों (First-generation learners) को पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक कौशल का अभाव रखते हैं (Deeksha, 2024)।
- **डिजिटल विभाजन:** यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2023-2024 का डेटा दर्शाता है कि बिहार के केवल 8.3% स्कूलों में कंप्यूटर लैब हैं, जबकि केरल में यह 68.7% है (Mehta, 2025)। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, बुनियादी ढांचे की यह कमी बिहार की लड़कियों को और अधिक हाशिए पर धकेल देती है, जिनमें से केवल 19.8% के पास अपना मोबाइल फोन है, जबकि लड़कों में यह आँकड़ा 43.7% है (Baig, 2024)।

राज्य के हस्तक्षेपों का मूल्यांकन: क्या साइकिल बदलाव का पहिया बनी?

बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए कई "उच्च-दृश्यता" (High-visibility) वाली कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। यह खंड, तीन सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (MBCY)

2006 में शुरू की गई इस योजना ने कक्षा 8 पास करने वाली प्रत्येक लड़की को हाई स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की। यह भारतीय विकास नीति के इतिहास में सबसे चर्चित और शोधित (Researchable) योजनाओं में से एक है।

- **पहुँच पर प्रभाव (Impact on Access):** इसे व्यापक रूप से भारत में सबसे सफल लैंगिक हस्तक्षेपों में से एक माना जाता है। मुरलीधरन और प्रकाश (2017) के शोध ने पाया कि इस योजना ने माध्यमिक विद्यालय में

लड़कियों के नामांकन में 32% की वृद्धि की और लैंगिक अंतराल को 40% तक कम कर दिया ((Muralidharan & Prakash, 2017)। साइकिल ने स्कूली शिक्षा की 'दूरी की लागत' (Distance Cost) को हल किया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख बाधा थी, जहाँ प्राथमिक स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल कम हैं।

- **सामाजिक प्रभाव:** नामांकन से परे, साइकिल **गतिशीलता एजेंसी** (Mobility Agency) का प्रतीक बन गई। समूहों में साइकिल चलाती लड़कियों ने उन सामंती और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी, जो महिलाओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करते थे। इसने लड़कियों को सार्वजनिक क्षेत्र में दृश्यमान (Visible) बना दिया (Tripathi & Kumari, 2022; Prakash, 2023))।
- **सीमाएँ:** जहाँ इसने पहुँच में सुधार किया, वहीं अधिगम प्रतिफलों से इसका सीधा संबंध कमजोर है। योजना लड़कियों को स्कूल तक तो ले आई, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि वहाँ पहुँचने के बाद वे सीखें। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मॉडल को शुरू में भ्रष्टाचार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, जहाँ पैसे का उपयोग गैर-साइकिल उद्देश्यों के लिए किया गया, हालाँकि बाद में शिविरों और भौतिक सत्यापन द्वारा इसे कम किया गया (KUMAR, 2012)।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

यह योजना स्कूल यूनिफॉर्म (पोशाक) के लिए नकद राशि प्रदान करती है।

- **पहचान और अपनापन:** ग्रामीण लड़कियों को "छात्रत्व" (Student hood) का बोध कराने में वर्दी योजना महत्वपूर्ण है। इसने कक्षा के भीतर दिखाई देने वाले वर्ग भेद को कम किया।
- **भ्रष्टाचार और रिसाव:** रिपोर्टों ने इस योजना में महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है। 'फर्जी नामांकन' के मामले सामने आए हैं, जहाँ स्कूलों ने वर्दी के फंड का गबन करने के लिए संख्या बढ़ाई (KUMAR, 2012)। सीएजी (CAG) और अन्य ऑडिट ने इन निधियों के वितरण में अनियमितताओं की ओर इशारा किया है (ET Government, 2021)।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY)

यह एक महत्वाकांक्षी **"पालने से लेकर स्नातक तक" (Cradle to Graduation)** सशर्त नकद हस्तांतरण (CCT) योजना है। यह विभिन्न चरणों पर वित्तीय मील के पत्थर का वादा करती है: जन्म पर, टीकाकरण पर, कक्षा 10 और 12 पास करने पर, और स्नातक होने पर एक महत्वपूर्ण राशि (पहले ₹25,000, अब बढ़ी हुई राशि 50,000) (Srinivasan, 2025; Reddy, 2021)।

- **उद्देश्य:** योजना का स्पष्ट उद्देश्य स्नातक स्तर की पढ़ाई को प्रोत्साहित करके विवाह में देरी करना और कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करना है (MKUY, 2025)।
- **कार्यान्वयन की विफलताएँ:** यह योजना नौकरशाही और लालफीताशाही से ग्रस्त है। लाभार्थी लाभ/फ़ंड प्राप्त करने में भारी देरी की रिपोर्ट करते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विफलताएँ, कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, और रिश्वत की माँग की खबरें आम हैं (Staff Reporter, 2025)।
- **रणनीतिक आलोचना:** जहाँ योजना का इरादा विवाह में देरी करना है, वहीं वास्तविकता यह है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और नौकरी की संभावनाओं के बिना, यह पैसा अक्सर सशक्तिकरण साधन के बजाय **"दहेज सब्सिडी" (Dowry Subsidy)** बन जाता है। यदि कोई लड़की स्नातक हो जाती है, लेकिन उसके पास रोजगार योग्य कौशल नहीं है (खराब शिक्षा गुणवत्ता के कारण), तो परिवार MKUY के धन का उपयोग उसके विवाह खर्चों का

भुगतान करने के लिए कर सकता है, जिससे उसी संस्था को मजबूती मिलती है, जिसे वह विलंबित करना चाहता है (Chatterjee, 2021)।

संरचनात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ

योजनाओं के बावजूद, गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएँ प्रगति के खिलाफ रुकावट या अवरोधक का काम करती हैं।

"विवाह बाजार" बनाम "श्रम बाजार"

बिहार में, महिला शिक्षा को अक्सर "श्रम बाजार" (Labour Market) के बजाय "विवाह बाजार" (Marriage Market) के चश्मे से देखा जाता है। माता-पिता लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि वे करियर बनाएँ, बल्कि इसलिए ताकि उन्हें "बेहतर पति" मिल सके। शिक्षा का यह "साधनपरक" (Instrumental) दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि एक बार "विवाह-योग्यता" की सीमा (अक्सर कक्षा 10 या 12) पूरी हो जाने पर, शिक्षा रोक दी जाती है (Gordon, 2021; Raj et al., 2019)।

- **बाल विवाह:** बिहार में बाल विवाह की दरें उच्च बनी हुई हैं। एनएफएचएस-5 (NFHS-5) का डेटा इसे सीधे ड्रॉप आउट दरों से जोड़ता है। आर्थिक झटके (जैसे बाढ़ या कोविड-19 महामारी) इसे और बढ़ा देते हैं, जिससे परिवार आर्थिक बोझ कम करने के लिए बेटियों की शादी जल्दी करने को मजबूर हो जाते हैं (Khanna & Kochhar, 2020)।
- **दोहरा बोझ (Double Burden):** किशोर लड़कियों को स्कूली शिक्षा और घरेलू कामकाज के "दोहरे बोझ" का सामना करना पड़ता है। लड़कों के विपरीत, जिन्हें पढ़ने के लिए घर के काम से छूट दी जाती है, लड़कियों से भाई-बहनों की देखभाल, खाना पकाने और सफाई की उम्मीद की जाती है, जिससे होम वर्क या स्व-अध्ययन के लिए बहुत कम समय बचता है (Kumari & Das, 2023)।

ढाँचागत हिंसा: शौचालय का प्रश्न

बिना कार्यात्मक शौचालय वाला स्कूल लड़कियों के खिलाफ **"ढाँचागत हिंसा" (Infrastructural Violence)** का एक रूप है।

- **आँकड़े बनाम वास्तविकता:** यूडीआईएसई+ 2024-25 का दावा है कि 97.2% स्कूलों में लड़कियों के शौचालय हैं (UDISE+, 2024-25)। हालाँकि, सीएजी (CAG) ऑडिट ने ऐतिहासिक रूप से "निर्मित" और "कार्यात्मक" शौचालयों के बीच भारी अंतर का खुलासा किया है। एक सीएजी (CAG) सर्वेक्षण में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में लगभग 40% शौचालय या तो अस्तित्वहीन थे या पानी/सफाई की कमी के कारण अनुपयोगी थे (Special Correspondent, 2020)।
- **प्रभाव:** कार्यात्मक, स्वच्छ और निजी शौचालयों की कमी, किशोर लड़कियों, विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान, की अनुपस्थिति का एक प्रमुख कारण है। यह "पीरियड पॉवर्टी" (Period Poverty) लड़कियों को हर महीने 3-5 दिन स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करती है, जिससे सीखने में अंतराल पैदा होता है। जो अंततः ड्रॉप आउट का कारण बनता है (Kumari & Das, 2023)।

सुरक्षा का अभाव

माध्यमिक विद्यालयों की "दूरी" जिसे पाटने में साइकिल ने जरूर मदद की है, मगर यह अभी भी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में एक सुरक्षा से जुड़ी चिंता का विषय है। और दूरदराज के क्षेत्रों में तो **"अंतिम मील" (Last Mile)** की कनेक्टिविटी

उत्पीड़न के जोखिमों से भरी है। यह डर माता-पिता को यौवन तक पहुँचते ही लड़कियों को स्कूल से निकालने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि "सम्मान/इज़्ज़त" को शिक्षा पर प्राथमिकता दी जाती है (Kumari & Das, 2023)।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था: "वोट बैंक" के साधन के रूप में योजनाओं का प्रयोग

बिहार की शिक्षा नीति का वर्तमान स्वरूप और सत्ताधारी शासन के द्वारा संचालित योजनाएँ आपस में एक-दूसरे से संबंधित है अर्थात प्रोत्साहन या कल्याणकारी योजनाएँ नए वोट बैंक या लाभार्थी वर्ग को बनाने से जुड़ी है, जो सत्ता के प्रति वफादार बनी रहे।

"लाभार्थी" वर्ग का उदय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचेत रूप से महिलाओं को एक विशिष्ट **"वोट बैंक"** के रूप में विकसित किया, जो **"जाति की राजनीति" (Caste Politics)** की सीमाओं को पार करता है। पारंपरिक पुरुष/जाति के सत्ता दलालों को दरकिनार करते हुए और सीधे महिलाओं और लड़कियों को लाभ (साइकिल, नकद) पहुँचाकर, उन्होंने **"मौन मतदाताओं" (Silent Voters)** का एक वफादार आधार या वर्ग तैयार किया (Srinivasan, 2025; Vibha Attri, 2025)।

- **दृश्यता की राजनीति (Politics of Visibility):** साइकिल योजना जैसी योजनाएँ राजनीतिक रूप से आकर्षक हैं, क्योंकि वे अत्यधिक दृश्यमान हैं। साइकिल चलाती लड़की विकास का एक ठोस प्रतीक है, जिसे मतदाता देख सकते हैं। इसके विपरीत, "बेहतर अधिगम परिणाम" या "बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण" अदृश्य हैं और उन्हें प्रकट होने में वर्षों लग जाते हैं।
- **लोकलुभावन जाल:** यह सरकार के लिए आउटकम (यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पढ़ सकें) के बजाय इनपुट (स्कूल बनाना, पैसा/वर्दी बाँटना) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन पैदा करता है। साइकिल बाँटने का राजनीतिक लाभ तत्काल मिलता है जबकि शैक्षिक सुधार का लाभ दूरस्थ और अनिश्चित होता है।

संरचनात्मक सुधारों का प्रतिरोध

"नियोजित शिक्षक" प्रणाली में सुधार के प्रयासों को कड़े राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। शिक्षक एक शक्तिशाली वोटिंग ब्लॉक हैं और चुनाव एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। कड़े जवाबदेही उपायों (जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति या सक्षमता परीक्षण) के साथ उन्हें अलग-थलग करने की भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रकार, सरकार अक्सर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए गुणवत्ता से समझौता करती है (Deeksha, 2024; Paran Amitava & Sharma, 2024) ।

निष्कर्ष और सुझाव: पहुँच से सशक्तिकरण की ओर (From Access to Empowerment)

निष्कर्षों का संश्लेषण

बिहार में बालिका शिक्षा की कहानी **अधूरी क्रांति** (Incomplete Revolution) की कहानी है।

1. **मात्रात्मक सफलता:** राज्य ने लड़कियों को स्कूल लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रारंभिक स्तर पर नामांकन में लैंगिक अंतराल लगभग समाप्त हो गया है। 2005 में राज्य की स्थिति को देखते हुए यह एक स्मरणीय उपलब्धि है।
2. **गुणात्मक विफलता:** एक बार जब लड़कियाँ प्रवेश करती हैं, तो प्रणाली उन्हें विफल कर देती है। उनका स्वागत खराब बुनियादी ढाँचे, अनुपस्थित शिक्षकों और एक ऐसे पाठ्यक्रम से होता है जो बुनियादी कौशल का निर्माण नहीं करता है। इसका परिणाम लड़कियों की एक ऐसी पीढ़ी है जो "स्कूली शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन शिक्षित नहीं" (Schooled but not Educated)।

3. **नीतिगत सीमाएँ:** साइकिल और वर्दी जैसे प्रोत्साहन आवश्यक तो हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। वे बहिष्कार के लक्षणों (गरीबी, दूरी) को संबोधित करते हैं, लेकिन मूल कारणों (पितृसत्ता, खराब स्कूल गुणवत्ता) को नहीं।

प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift) के लिए सिफारिशें

भागीदारी से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने के लिए, बिहार को सुधारों की दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता है:

- **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) पर ध्यान:** राज्य को निपुण भारत (NIPUN Bharat) मिशन के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। इस आधार के बिना, माध्यमिक नामांकन अर्थहीन है।
- **शिक्षक जवाबदेही और समर्थन:** केवल "ऐप-आधारित" उपस्थिति पुलिसिंग से आगे बढ़कर वास्तविक शिक्षक समर्थन, प्रशिक्षण और तदर्थ अनुबंधों के बजाय योग्य स्थायी कर्मचारियों के साथ रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।
- **बुनियादी ढाँचा ऑडिट:** स्कूल शौचालयों और सुरक्षा बुनियादी ढाँचे का एक स्वतंत्र, तृतीय-पक्ष सामाजिक ऑडिट आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूडीआईएसई+ का डेटा वास्तविकता से मेल खाये।
- **व्यावसायिक एकीकरण:** माध्यमिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल (आईटी, कोडिंग, स्वास्थ्य सेवा) को एकीकृत करना ताकि "विवाह बाजार" की मानसिकता को तोड़ा जा सके और शिक्षा को ठोस आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा जा सके।
- **गुणवत्ता के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति:** राजनीतिक नेतृत्व को मतदाताओं को यह समझाने के लिए राजनीतिक पूंजी खर्च करनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक अधिकार है, न कि केवल पहुँच। "वोट बैंक" को केवल मुफ्त सुविधाओं की नहीं, बल्कि सीखने की माँग करनी चाहिए।

अंत में, बिहार की लड़कियों ने राज्य द्वारा प्रदान की गई साइकिलों पर लंबा सफर तय किया है। लेकिन वास्तविक समानता और सशक्तिकरण की मंजिल तक पहुँचने के लिए, उस सड़क अर्थात शिक्षा प्रणाली की मरम्मत/सुधार किए जाने की जरूरत है, जिस पर वे चल रही हैं।

संदर्भ (References)

1. *ASER 2022 National Findings*. (2023).
2. https://img.asercentre.org/docs/ASER%202022%20report%20pdfs/allindiaaser202217_01_2023final.pdf
3. *Annual Status of Education Report 2023*. (2023). https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/annual-status-of-education-report-2023
4. Baig, A. (2024, January 23). *ASER 2023 uncovers alarming gaps in rural youth education, digital access, skills; experts suggest remedial measures - IndiaTomorrow*. IndiaTomorrow. https://indiatomorrow.net/2024/01/23/aser-2023-uncovers-alarming-gaps-in-rural-youth-education-digital-access-skills-experts-suggest-remedial-measures/
5. Chatterjee, R. (2021, July 2). *Mukhyamatri Kanya Utthan Yojana: Bihar's Step Towards Revolutionizing Women's Education*. Youth Ki Awaaz. https://www.youthkiawaaz.com/2021/07/mukhyamantri-kanya-utthan-yojana-bihars-step-towards-revolutionizing-womens-education/
6. Deeksha, J. (2024, November 7). *Bihar is using an app to track teachers' attendance – much to their anger*. Scroll.in. https://scroll.in/article/1075292/bihar-is-using-an-app-to-track-teachers-attendance-much-to-their-anger
7. ET Government. (2021, December 11). *Bihar govt punished around 200 officials for corruption in Central welfare schemes: Minister*. ETGovernment.com; PTI. https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/bihar-govt-punished-around-200-officials-for-corruption-in-central-welfare-schemes-minister/88220406
8. Gordon, R. (2021). 'Your mind becomes open with education': exploring mother's aspirations for girls' education in rural Bihar. *Compare*, 1–18. https://doi.org/10.1080/03057925.2021.1976616
9. Khanna, M., & Kochhar, N. (2020). *Natural hazards and child marriages: A case study from Bihar*. UNW WRD Knowledge Hub. https://wrd.unwomen.org/explore/insights/natural-hazards-and-child-marriages-case-study-bihar
10. Kripalani, M. (2025, November 13). *Election Diaries: Bihar 2025 Women, Welfare, Work*. Gateway House. https://www.gatewayhouse.in/election-diaries-bihar-2025-women-welfare-work/
11. Kumar, A. (2025, January 28). *ASER Report: Bihar joins national trend to show improvement, but still long way to go | Education*. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/education/news/aser-report-bihar-joins-national-trend-to-show-improvement-but-still-long-way-to-go-101738070081698.html
12. KUMAR, R. (2012, December 20). *Transparency key in study scheme - Govt to disburse funds in camps to check corruption*. Telegraphindia.com; Telegraph India. https://www.telegraphindia.com/bihar/transparency-key-in-study-scheme-govt-to-disburse-funds-in-camps-to-check-corruption/cid/350402
13. Kumari, A., & Das, J. (2023). Women Empowerment through Education in Bihar. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, *1*(3) Year: 2023, ISSN: 2992-894X
14. Mehta, A. C. (2025, March 19). *A Comparative Analysis of Bihar and Kerala Using UDISEPlus 2023-24 Data | Education for All in India*. Education for All in India. https://educationforallinindia.com/a-comparative-analysis-of-bihar-and-kerala-using-udiseplus-2023-24-data/
15. Mehta, A. C. (2024). *About 1.5 crore children in Classes 1-8 dropped out between 2021-22 & 2022-23 and 54 lakh between 2022-23 & 2023-24 UDISE+ 2022-23 & 2023-24: Preliminary Analysis**. https://educationforallinindia.com/wp-content/uploads/2025/01/UDISE_2022-23-_2023-24_analysis_aruncmehta.pdf
16. *Ministry of Education releases report on Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2024-25 on school education of India*. (2024). Pib.gov.in. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161543&reg=3&lang=2
17. Muralidharan, K., & Prakash, N. (2017). Cycling to School: Increasing Secondary School Enrollment for Girls in India. *American Economic Journal: Applied Economics*, *9*(3), 321–350. https://doi.org/10.1257/app.20160004

18. Paran Amitava, & Sharma, K. (2024, February 7). *Bihar Turns its Back on School Education*. The India Forum; TheIndiaForum. https://www.theindiaforum.in/forum/bihar-turns-its-back-school-education
19. Prakash, N. (2023, July 19). *An Indian bicycle program is having a revolutionary impact on the lives of young girls*. College of Social Sciences and Humanities. https://cssh.northeastern.edu/an-indian-bicycle-program-is-having-a-revolutionary-impact-on-the-lives-of-young-girls/
20. Raj, A., Salazar, M., Jackson, E. C., Wyss, N., McClendon, K. A., Khanna, A., Belayneh, Y., & McDougal, L. (2019). Students and brides: a qualitative analysis of the relationship between girls' education and early marriage in Ethiopia and India. *BMC Public Health*, *19*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-018-6340-6
21. Reddy, S. (2021, August 18). *Mukhyamantri Kanya Utthaan Yojana (MKUY)*. Vikaspedia.in; Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). https://schemes.vikaspedia.in/viewcontent/schemesall/state-specific-schemes/welfare-schemes-of-bihar/mukhyamantri-kanya-utthaan-yojana--mkuy-?lgn=en
22. Special Correspondent. (2020, September 23). *40% of toilets surveyed by CAG in government schools non-existent, unused*. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/40-of-toilets-surveyed-by-cag-in-govt-schools-non-existent-unused/article32680816.ece
23. Srinivasan, V. (2025, November 27). *Bihar women's vote was for dignity, not freebies | Hindustan Times*. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/opinion/bihar-women-s-vote-was-for-dignity-not-freebies-101764256631457.html
24. Staff Reporter. (2025, July 12). *Students Allege Bribes Demanded for Kanya Utthan Scheme Enrolment Amid Delays and Dysfunction*. Patna Press. https://patnapress.com/kanya-utthan-yojana-bribery-allegations/
25. Sharma, G. (2023). *WOMEN EMPOWERMENT THROUGH EDUCATION IN BIHAR*. http://dx.doi.org/
26. Sharma, S. (2025, October 12). *Why Bihar's education system needs to be on the ballot this election: Dropout rates, inequality, and a failing future*. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/why-bihars-education-system-needs-to-be-on-the-ballot-this-election-dropout-rates-inequality-and-a-failing-future/articleshow/124501349.cms
27. Team, C. (2024, January 28). *Annual Status of Education Report (ASER) 2023*.
28. https://www.pmfias.com/annual-status-of-education-report-aser-2023/
29. Tripathi, S., & Kumari, P. (2022). Impact of Mukhyamantri Balika Cycle Yojana on rural school going girls. *~ 738 ~ the Pharma Innovation Journal*, *12*, 738–739. https://www.thepharmajournal.com/archives/2022/vol11issue12S/PartJ/S-11-12-37-703.pdf
30. *UDISE+*. (2025). Udiseplus.gov.in. https://dashboard.udiseplus.gov.in/
31. Vibha Attri. (2025, November 21). *How welfare delivery shaped, but did not decide, Bihar's elections*. The Hindu. https://www.thehindu.com/data/how-welfare-delivery-shaped-but-did-not-decide-bihars-elections/article70302781.ece